Indian J.Soc & Pol. 03(03):2016:55-58 **ISSN 2348-0084 (PRINT)**
(Special Print Issue: September, 2016) **ISSN 2455-2127(ONLINE)**

वर्तमान भारतीय राजनीतिः दशा और दिशा

लाखा राम चौधरी[1],
[1]कार्यालय प्रधान महालेखाकार,लेखापरीक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत

ABSTRACT

लोकतंत्र में जनाकांक्षा की प्रधानता होती है, सैद्धान्तिक रूप में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति नियम निर्धारण तथा इस व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों द्वारा व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। जनता समष्टि की अभिव्यक्ति है। वह विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय में बंटी हुई दिखाई पड़ती है जिससे उनमें सापेक्ष वृहत्तर हित के चिन्तन का अभाव हो रहा है तथा संकीर्णता की भावना बलवती होती जा रही है। स्वतंत्रता के पूर्व देश में संकीर्णता को छोड़कर स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्य के प्रति सभी का समर्पण था। अपनी तमाम विकृतियों के पश्चात् भी भारतीय लोकतंत्र की विश्व के सफलतम देशों में गिनती की जाती है क्योंकि जब भारत में लोकतंत्र स्थापित किया था तो तत्कालिक परिस्थितियां बहुत ही विषम थी। आज भारतीय लोकतंत्र दिशाहीन प्रतीत हो रहा है। जैसा कि लोकतंत्र का तात्पर्य, जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन माना जाता है। लेकिन आज धनिकों, बाहुबलियों एवं अपराधियों के चंगुल में फंस गया और जनता की स्थिति दास या सेवक की हो गई है। राजनीतिक दल भी दिशाहीन, विचारधारा रहित प्रतीत हो रहे हैं। आज राजनीतिक दल आम जन को भेड़–बकरियों की तरह हांकने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कहीं धर्म, तो कहीं जाति, बिरादरी का, कहीं प्रलोभन, तो कहीं डंडे का भय।

***KEY WORDS:** भारत, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, लोकतंत्र*

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में राजनीतिक स्थिरता के प्रयास शीर्षोन्मुखी है। जनसंख्या का दबाव, बढ़ती हुई जनकथाएं, वैज्ञानिक प्रगति, उदारीकरण, निजीकरण एवं भूण्डलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक सम्बन्धों का प्रसार, राष्ट्रीय सम्प्रभुता के बदलते आयाम और अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश इन सभी ने भारतीय राजनीति के स्थापित मानकों को कदाचित विचलित किया है तथा नए मानकों के लिए पथ प्रशस्त किया है। राष्ट्र की प्रगति में सभी की गरिमा सुनिश्चित होती है। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक सहभागिता की स्थितियां निर्मित होती हैं। देश के नागरिकों द्वारा मताधिकार के प्रयोग द्वारा सत्ता का परिवर्तन हमेशा शान्तिपूर्ण ढंग से आम निर्वाचन के द्वारा होता है। भारतीय राजनीति सभी वर्गो के लिए देश की आत्मा एवं आवाज है। महिलाएं तथा ग्रामीण जनता को स्वशासन का अधिकार देकर भारतीय लोकतंत्र ने जता दिया है कि वह प्रगतिशील एवं जीवन्त है। कल्याणकारी राज्य की अवधरणा के अन्तर्गत बच्चों, वृद्धों, विकलांगों को लगातार सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्तमान में नेतृत्व के लिए मानक चारित्रिक व्यवस्था का निर्धारण नहीं है तथा निर्धारित मानकों में भी तमाम छिद्र है। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने का कारगार उपाय नहीं हो सका है। कहने को राजनीतिक दलों के कुछ सिद्धान्त है, परन्तु व्यावहारिक धरातल पर उनकी हकीकत में पर्याप्त अन्तर है। जिस किसी प्रकार सत्ता हथियाना आदर्श तथा लक्ष्य हो गया है। दलीय सिद्धान्त सामूहिक न होकर विशिष्ट व्यक्तियों के कथोपकथन इच्छा की परिक्रमा करने वाला रह गया है। ऐसी स्थिति में शास्त्रवर्णित गुणों से युक्त नेतृत्व के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए मानक नियम निर्धारण तथा उसे कार्यान्वित कराने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र की कल्पना करते हुए महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि राजनेताओं ने कभी नहीं चाहा था कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में चला जाए जो कि सच्चरित्रता, सदाचार, संयम, नैतिकता आदि गुणों के खिलाफ जीवन शैली रखते हैं। जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग संसद में जायेंगे तो लोकतंत्र और राजनीति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। हम सभी भारतीयों की आस्था और भरोसे का प्रतीक है लेकिन जबसे गठबंधन की राजनीति शुरू होती है, तभी से संसदीय प्रक्रिया प्रभावित होनी शुरू हुई और अपराधी प्रवृति के लोगों का महत्व और बढ़ता गया है। चुनाव क्षेत्रों में अपनी अपराधिक प्रवृति व धनबल के आधार पर संसद व विधानमंडल में पहुँचकर संसदीय गरिमा को बेचते हैं। आज संसद के संचालन में यही घटक गतिरोध ला रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की होगी कि इस तरह संसद की गरिमा को क्षति पहुँचेगी।

1.Corresponding Author

आज राजनीति में जाना एक तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। ये सदस्य संसद और विधानमंडल में जाने के पश्चात् समाज और देशहित को दरकिनार करके औद्योगिक घरानों का हित साध रहे हैं। साथ ही साथ सत्ता प्राप्त करने की लालसा के लिए झुण्ड राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय हित की जगह क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता तथा अन्य ऐसे तत्त्वों को उठा रहे हैं जो संसदीय प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि संसद सदस्यों में आत्म चेतना की कमी है। आज के समय में यह हर किसी के द्वारा गौर किया जा रहा है कि अब संसदीय राजनीति में भाषा की कोई मर्यादा शेष नहीं रह गयी। सामाजिक अवमूल्यन के इस दौर में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी दूसरी पार्टी के नेता के विरूद्व किसी भी स्तर तक जाकर भाषा का प्रयोग कर रहा है। वह सारी हदें पार कर रहा है। साथ ही अधिकांश सांसद अपनी स्थानीय विकास निधि को भी उचित प्रकार एवं सही समय पर खर्च नहीं करते हैं जो यह दर्शाता है कि उनकी अपने क्षेत्र के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है।

भारतीय राजनीति में भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए असीमित लोभ के वशीभूत अधिकाधिक धनसंग्रह की प्रवृति का नग्ननृत्य सर्वत्रा दृष्टिगोचर हो रहा है, सामाजिक स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अनैतिक रूप से धनार्जन करने वाले व्यक्ति का क्षणिक, स्वार्थवश लोग यशोगान की स्थिति में आ गए हैं। अनैतिक मूल्यों की निन्दा अथवा उसे हतोत्साहित करने की प्रवृति नगण्य हो गई है। प्राचीन काल के ग्रंथों, संदर्भों में सम्पति संग्रह के अधिकार के साथ यह दिशा निर्देश है कि जिसके घर में तीन वर्ष के लिए या उससे अधिक भृत्य पोषण के लिए पर्याप्त धन हो उसे ज्योतिष्टोम कर सोमपान करना चाहिए।

वर्तमान समय में राजनीतिक दल क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, हिंसा, वित्त की आवश्यकता, लोकतंत्र का अभाव, महिलाओं की भागीदारी, पार्टी सदस्यों का प्रशिक्षण, सिद्धान्तों और राजनीतिक मूल्यों का अभाव, प्रचार अभियान का तरीका, विघटन एवं गठबंधन की राजनीति, लम्बा चौड़ा मंत्रिमंडल, जातिवाद, अपराधीकरण, प्रशासन, नेतृत्व क्षमता जैसी समस्याओं के दलदल में बुरी तरह से फँसे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की जातिवादी राजनीति का जहर अब राष्ट्रीय दलों में भी फैला दिख रहा है। जातिवाद समाजिक सच्चाई है लेकिन हमारे नेताओं ने उसका राजनीतिक उपयोग करते –करते उसे विघटनवाद के कगार तक पहुँचा दिया है। जैसे लोकपाल में आरक्षण होना, लोकसभा में न्यायपालिका मे आरक्षण की बात करना। भविष्य में यदि सेना, खेलों में भी आरक्षण की माँग सुनी जाये, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। राजनीति में जातिवाद का नया जोश पिछड़ावाद और अतिपिछड़ावाद के रूप में सामने आया है।

आज महात्मा गाँधी का कथन संसदीय शासन व्यवस्था में संसद की स्थिति वेश्या और बांझ की है, जो चरितार्थ हो रही है फिर भी अगर संसदीय लोकतंत्र की साख को बचाना है तो इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और राजनीति में इनकी भागीदारी के साथ ही साथ इनके नैतिक मूल्यों का संचय जरूरी है। अरस्तू ने ठीक कहा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना उस राज्य के नागरिकों के चरित्र से हो सकती है। आज जरूरी है आम जनता की भागीदारी बढ़े और अपने नेता का चुनाव ईमानदारी से देश हित के लिए करें, जिससे कि संसदीय प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं राजनीतिक दलों को भी अपने टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रबंध्न और प्रचार में ईमानदारी बरतनी चाहिए, अच्छे उम्मीदवार को टिकट दें, अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में आनुवंशिक आधार पर न रखें बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से ही चुनाव करें जिससे कि संसदीय गरिमा को बचाया जा सके।

भारत जैसे दुनिया के विशालतम लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक, कार्यकारी एवं न्यायिक सत्ता कुर्सी पर बैठे लोगाों को प्रचुर शक्तियां प्रदान करती है। भ्रष्टाचार का जन्म कहीं न कहीं सत्ता लोलुप्ता का ही परिणाम होता है। सत्ता की भूख जब–जब हदें पार करती है तो वह अकूत ताकत, बेशुमार सम्पति तथा वह सब कुछ जिसे हमारी परम्परा त्याज्य समझती थी, को समेट लेना चाहती है। भारत में भ्रष्टाचार का प्रसार सरकारी महकमे में निर्वाचित राजनीतिज्ञों से लेकर उच्च नौकरशाही और निम्न नौकरशाही के विभिन्न स्तरों पर लम्बवत रूप में अर्थात ऊपर से नीच तक फैला है। भ्रष्टाचार का सर्वाधिक दुष्प्रभाव देश की गरीब जनता पर पड़ता है। यदि घोटाले और काले धन के रूप में जमा रकम को जब्त कर गरीब बच्चों की स्कूली शिक्षा, मुफ्रत भोजन, किताब, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च किये जायें, तो हम भारत को शीघ्र ही विकसित देश की श्रेणी में पहुँचा सकते हैं। अतः इन नेताओं को चुनने वाली जनता अपने आंख, कान को खुले रखकर इस प्रदूषण को कम करने के लिए यह संकल्प लेना होगा कि वे अपना कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत कभी नहीं देंगे, थोड़ी परेशानी सहेंगे, थोड़ा नुकसान भरेंगे, थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन भ्रष्टाचार के आगे घुटने नहीं टेकेंगे।

वर्तमान में देश की सबसे बड़ी चुनौतियां राजनीतिक स्तर पर मौजूद है। स्थिरता, परिपक्वता के बावजूद हमारी राजनीतिक प्रणाली में गहरी विसंगतियां पैदा हो गई हैं।

राजनीति धर्म, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, भ्रष्टाचार, अलगावाद, पृथकतावाद जैसे संकीर्ण मुद्दों पर आधरित हो गई है। चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है पर आज भी महिलाएं कन्याभ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी तमाम समस्याओं से ग्रसित है। क्षेत्रीयता, आर्थिक असमानता, अपर्याप्त शिक्षा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, व्याधि, प्रदूषण, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवसरहीनता जैसी समस्याओं का समाधान सुशासन एवं सुनियोजित विकास से ही संभव है। राजनेताओं की दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, सामाजिक संरचना की जटिलता शिथिल करने तथा राष्ट्रीय उपलब्धियों को जनमानस तक पहुँचाने में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता का लाभ तभी है जब इसके सफल संचालन में देश के सभी नागरिक योगदान दें।

हाल ही में देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यशस्वी प्रधनमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने 8 नवम्बर, 2016 से 500 और 1000 के नोट बंद करके उसके स्थान पर 500 व 2000 का नया नोट शुरू किया, जिससे देश की 86 प्रतिशत मुद्रा चलन से बाहर हो गई। मोदी जी द्वारा ऐसा कठोर कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य काला धन, जाली मुद्रा, आतंकवाद, नक्सलवाद, तस्करी व ड्रग्स के लिए फंडिंग तथा अन्य देश विरोधी गतिविधियों में इनके इस्तेमाल पर नकेल कसने के लिए ऐसा किया गया, जिसका विरोध केवल विपक्षी राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं जबकि इसके समर्थन में देश की अध्किांश जनता खड़ी है। इतना बड़ा कदम देश में पहली बार उठाया गया जिसमें सीधे तौर ईमानदारों की बले–बले हो रही है जबकि बेईमानों को कठोर से कठोर सजा का अहसास हो रहा है। इस देश हितैषी मुद्दे पर भी सभी राजनीतिक दल एकमत नहीं हैं पूरा विपक्ष इसके खिलाफ अपने निजी राजनैतिक स्वार्थ के लिए खड़ा है जो भविष्य में देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में डकैत, लठैत, सामन्त, आलाकमान जैसे शब्दों का राजनैतिक विमर्श में बाहुल्य बेहद चिन्ताजनक है।

वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नक्सलवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है। स्वतंत्राता के बाद भारत की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की यथास्थिति को जिन आन्दोलनों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, उनमें नक्सलवादी आन्दोलन प्रमुख है। अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह आन्दोलन भारतीय लोकतंत्रा के लिए एक गम्भीर समस्या के रूप में उभरा है। आतंकवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए नासूर है। आतंकवाद का जो स्वरूप भारत में दिखाई पड़ता है वह स्थूल तौर पर 'जिहादी' है। आतंकवाद ने भारत में राजनीतिक संवाद एवं चेतना के धरातल पर एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है। आतंकवाद ने वर्गीय विभाजन को धर प्रदान की हैं इससे धर्मिक कट्टरता बढ़ी है। एक वर्ग विशेष के लोगों से घृणा की जा रही है। यह भारतीय समाज की एक नियति बन गई है। हाल ही में संसद भवन पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरू, ताज होटल पर आतंकी हमले के जीवित आरोपी अजमल कसाब तथा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी बुरहान वानि के जनाजा में लाखों की भीड़ इकट्ठी होना और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय, पं. बंगाल में देश विरोधि नारे लगाने वाले कुछ भ्रमित विद्यार्थियों के साथ देश के नामचीन राजनेताओं, मीडिया हाऊसों, फिल्मी हस्तियों का खड़ा होना, देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर अँगुली उठाना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें सोचनें को मजबूर कर देते हैं। आखिरकार ऐसे लोग देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और इस देश का भविष्य क्या होगा?

इस प्रकार अनुचित प्रकार से अर्जित धन देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक तथा राष्ट्र की सामाजिक समरसता, आदर्शो को नष्ट करने वाला प्रमुख कारक है। भारतीय राजनीति की चिन्तनीय वर्तमान दशा में नेतृत्व के लिए योग्यता हेतु मानक का प्रयोग तथा अन्यायार्जित धन सम्पदा का राष्ट्र के प्रति हरण कर राजनीति की वर्तमान दशा को सुधारा जा सकता है। देश के भींतर और बाहर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, इससे निपटने के लिए जनता के दिलों को जीता जाये, वह भी राजनीति के माध्यम से, आर्थिक विकास, त्वरित न्याय और जन–शिकायतों की तीव्र सुनवाई हो, ये सब बेहतर प्रशासन की कुंजी है। अहिंसक जन आन्दोलनों की प्रकृति जटिल होने के कारण इनसे निपटने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। देश में लोकतंत्र की सफलता और उसे जीवन्त रखने के लिए एक बार फिर धरती पुत्राों के निकट जाना होगा, उनकी कठिनाइयों को जानना होगा। अब इस जनतंत्रीय व्यवस्था में 'तन्त्र' तो विभिन्न प्रकार के मिल जायेंगे किन्तु 'जन' तो दूर तक नजर नहीं आता है। जन को इसे पाने के लिए संघर्ष करना होगा।

वस्तुतः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कई तरह की नवीन प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई हैं, इनमें प्रमुख हैं– क्षेत्रवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, पर्यावरण संकट,

भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, दूरस्थ नियंत्रित प्रधनमंत्री, गठबंध्न राजनीति, नौकरशाहों का दलों की तरफ आकर्षण, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। इनमें से क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद भारतीय राजनीति के ऐसे मुद्दे हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। गठबन्धन की राजनीति परिस्थितियों के गर्भ से उत्पन्न होती है। राजनीतिक गठबन्धन बेशक सत्ता सुख सुलभ कराते हैं लेकिन इसमें शामिल घटक दलों की बार–बार की दोस्ती, धोखाधड़ी एवं सौदेबाजी ही गठबन्धन राजनीति की कड़वी सच्चाई बन गई है। यह राष्ट्रीय और राजनीतिक दायित्वों के प्रति गैर जिम्मेदार और गैर जवाबदेह होता है। वर्तमान में राष्ट्र हित में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की बनती संस्कृति को रोकना होगा और उनकी भूमिका को भी सीमित करना होगा जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे और केन्द्र शक्तिशाली स्थिति में रह सके, जिसे क्षेत्रीय पार्टी अपनी संकीर्ण माँगों के लिए झुका न सके। महिला आरक्षण विधेयक भी भारतीय राजनीति का ज्वलन्त विषय बन गया है। महिलाएँ अपने इस अधिकार की प्राप्ति हेतु एकजुट होकर संघर्ष करें तभी उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। पंचायतों में महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण उनके सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा। स्वतंत्रता के उपरान्त जाति भारतीय राजनीति का निर्धारक तत्व रहा है। आज राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए जातिवाद के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण एवं सामाजिक विखण्डन लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के लिए हितकर नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सफल बनाने में संसद, न्यायिक प्रक्रिया, सतर्क मीडिया, जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग, चुनाव आयोग और संगठित कार्यकारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राजनीति की दशा पर विचार किया जाए तो राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण, उत्तरदायित्व का अभाव, धनशक्ति और भुजबल का प्रभुत्व, धर्मवाद, जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों का दमन, क्षेत्रवाद, भाषावाद एवं लिंगभेद का कुप्रभाव जैसी त्रुटियां सामने प्रमुख रूप से आती हैं। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दशा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में आतंकवाद एवं व्यापक भ्रष्टाचार है जिसने देश को अपने गिरफ्त में ले रखा है। जिसका उपचार गाँधीवादी मूल्यों के द्वारा किया जा सकता है।

संदर्भ

गोस्वामी, भालचन्द 2012: विधि और सामाजिक न्याय अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़

प्रियंवद 2005: भारतीय राजनीति के दो आरव्यान, हिंद पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली

सेंगर, शैलेन्द्र 2009: भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, गुंजन प्रकाशन, नई दिल्ली

राय, अरूंधति 2012: कठघरे में लोकतंत्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

गोस्वामी, भालचन्द्र 2013: भारतीय न्याय प्रणाली अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़

विप्लव, नरेश 2012: लोकतत्र के प्रमुख स्तम्भ, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ

सेंगर शैलेन्द्र 2015: भारतीय प्रशासन बदलते आयाम, कविता बुकसैंटर, दिल्ली

सक्सेना, हरिशरण 2009 : संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, पल्लवी पब्लिकेशन्स, हरियाणा

सुध, खुशबू 1999: धर्म राजनीति एवं मूल्यहीनता, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर

पाण्डेय, अरूण 2000: हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

दुबे, एम.पी.: धर्मनिरपेक्षवाद और भारतीय प्रजातंत्र, नेशनल पब्लिकेशिन हाउस, नई दिल्ली

सिंह, महेश्वर 2000: भारतीय लोकतंत्र समस्याएं व समाधान, साहित्यगार, जयपुर

जैन, कमलेश 2001: न्यायपालिका कसौटी पर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

कश्यप, सुभाष 2010: हमारी संसद, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली

टंडन, बिशन 2009: जनतंत्र और प्रशासन, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली

गजराज, पदम सिंह 2014: चेतना गुजरात: भारतीय राजनीति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और चुनौतियां, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

सोमरा, कर्णसिंह 1992: साम्प्रदायिक सदभाव एवं राजनीतिक चेतना, प्रिन्टवेल, जयपुर

त्रिपाठी, ममता मणि 2013: समकालीन भारतीय राजनीति के मुद्दे समस्या एवं समाधान, भारती पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैजाबाद

बसु, दुर्गादास: भारत का संविधन: एक परिचय प्रेटिंस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली।